

## राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने अपने केस डेटा को [राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड \(NJDC\)](#) पर एकीकृत किया है।

- जनता को मामलों की पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिये 'ओपन डेटा पॉलिसी (ODP)' के हिससे के रूप में NJDC के साथ एकीकरण।
- ODP नीतियों का एक समूह है, जो सरकारी डेटा को सभी के लिये उपलब्ध कराकर पारदर्शिता, जवाबदेही और मूल्य निर्माण को बढ़ावा देता है।

### राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDC):

- परिचय:**
  - NJDC पोर्टल देश भर के न्यायालयों के लंबित और नपिटए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है।
  - यह [ई-कोर्ट परियोजना](#) के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाया गया 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों, नरिण्यों एवं मामले के विवरण का एक डेटाबेस है।
  - इसकी मुख्य विशेषता यह है कि डेटा वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है और इसमें तालुका स्तर तक का वसित डेटा होता है।
    - इसे [ई-कोर्ट परियोजना के चरण II](#) के भाग के रूप में बनाया गया था, जो एक [केंद्र परियोजति योजना](#) है।
  - वर्तमान में वारी 23.81 करोड़ मामलों तथा 23.02 करोड़ से अधिक आदेशों/नरिण्यों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- NJDC का विकास:**
  - इस प्लेटफॉर्म को [राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र \(NIC\)](#) द्वारा कंप्यूटर सेल, [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) की रजिस्ट्री की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ समन्वय से विकसित किया गया है जिसमें एक इंटरैक्टिव इंटरफेस तथा एनालिटिक्स डैशबोर्ड शामिल है।
- महत्त्व:**
  - NJDC मामलों की पहचान, प्रबंधन तथा लंबित मामलों को कम करने के लिये एक नगिरानी उपकरण के रूप में काम करता है।
  - यह न्यायिक प्रक्रियाओं में वशिष्ट बाधाओं की पहचान करने में मदद करता है। उदाहरण के लिये, यदि किसी वशिष्ट राज्य में भूमि विवादों की संख्या बढ़ जाती है, तो इससे नीति निर्माताओं को यह पता लगाने में मदद मिलती है क्या उस वशिष्ट कानून को अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है।
  - यह कानून के वशिष्ट कषेत्रों से संबंधित इनपुट उत्पन्न करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिये, भूमि विवाद से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिये 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा को NJDC के साथ जोड़ा गया है।

### वर्तमान में मामलों की लंबितता की स्थिति:

- वर्ष 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 64,854 है।
- अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में 5,412 मामले दाखल किये गए और 5033 मामलों का नपिटारा किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय में तीन जजों वाली पीठ के पास 583 मामले, पाँच जजों की पीठ के पास 288 मामले, सात जजों की पीठ के पास 21 मामले और नौ जजों की पीठ के पास 135 मामले लंबित हैं, जिनमें से सभी दीवानी मामले हैं।

### ई-कोर्ट परियोजनाओं के तहत अन्य पहलें

- केस इनफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर
- [आभासी न्यायालय](#)
- [वीडियो-कॉन्फरेंसिंग](#)
- राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (National Service and Tracking of Electronic Processes-NSTEP)
- न्यायालय की दक्षता में सुधार के लिये सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट पोर्टल

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में न्यायकि पुनरीक्षण का अर्थ है (2017)

- (a) वधियीं और कार्यपालकि आदेशों की संवैधानकिता के वषिय में प्राख्यापन करने का न्यायपालकि का अधकिार ।
- (b) वधिानमंडलों द्वारा नरिमति वधियीं के प्रज्जान को प्रश्नगत करने का न्यायपालकि का अधकिार ।
- (c) न्यायपालकि का सभी वधियाी अधनियिमनों के, राष्ट्रपतिद्वारा उन पर सहमतिप्रदान कयि जाने के पूरव, पुनरीक्षण का अधकिार ।
- (d) न्यायपालकि का समान या भन्नि वादों में पूरव में दयि गए स्वयं के नरिणयों के पुनरीक्षण का अधकिार ।

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-judicial-data-grid-1>

